

मुरैना जिले में ग्रामीण आर्थिक विकास का इतिहास (1992-2002)

सारांश

मुरैना जिला मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र बहुत समय से दस्यु समस्या से पीड़ित होने के कारण पिछड़ा रहा है, इसके कारण क्षेत्र में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, वेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियाँ आदि हैं। मुरैना जिले में आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाला एक मात्र तथ्य प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ही नहीं है वरन् प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग भी आवश्यक है। भूमि, पानी, जलवायु एवं वनस्पतियाँ प्रकृति की अनमोल संपदा हैं जिन पर प्रत्येक जीवधारी जीविकोपार्जन हेतु निर्भर है। अतः आने वाली पीढ़ियों के लिये इन संपदाओं का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। मुरैना जिले की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। मुरैना जिले को विकसित जिला बनाने के लिए गाँवों का विकास आवश्यक है।

जिले की सबसे बड़ी समस्या गाँवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होना था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार गाँव में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएँ यथा शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पानी आदि के लिए प्रयास करती रही है। मुरैना जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति कृषि, सिंचाई, पशुपालन, उद्योग-धन्धे तथा फसल प्रतिमान पर निर्भर करती है। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित योजनाएँ तथा विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूह आधारित कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं इन कार्यक्रमों के चलते मुरैना जिले की तस्वीर काफी हद तक बदली है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सड़क सुविधाओं का विकास हुआ है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, पंचायतीराज।

प्रस्तावना

मुरैना जिले का मानव समाज परंपरावादी और अंधविश्वासी है। जो कोई भी प्राचीन परंपरा और अंधविश्वास प्रचलित है, उन्ही के आधार पर भावी पीढ़ी के सम्पूर्ण क्रियाकलाप होते रहते हैं। प्राचीन परंपरा और अंधविश्वास में से एक सजीव और प्रत्यक्ष उदाहरण मुरैना जिला और उसकी सहायक नदियों द्वारा होने वाले अपरदन की स्वतंत्रता में बाधा न डालना भी है।

जिन्दगी के दो बुनियादी सवाल हैं –रोजी और रोटी। रोजी और रोटी के अन्तर्गत कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनका सीधा संबंध जिन्दगी से है क्या? रोजी से रोटी मिल जाने पर अथवा रोटी के लिए रोजी मिल जाने पर मनुष्य संतोष की सांस लेता है। जीवन के विस्तृत पल पर नजर दौड़ने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें जीवन में संतोष, शान्ति नहीं मिलती है। हम इसके साथ-साथ कुछ और चाहते हैं, जिसको पाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और जिसके लिए वह जीवन में प्रत्येक प्रकार की कुर्बानी कर सकता है इसका आशय यह है कि रोजी, रोटी दे देती है, परन्तु इसमें संतुष्टि नहीं होती है। हम उसके साथ-साथ सामाजिकता भी चाहते हैं। अतः इसके लिए पूरे देश का एक साथ (ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में) विकास होना आवश्यक है परन्तु भारत में अधिकांश लोग ग्रामों में निवास करते हैं। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार शिला ग्रामीण विकास है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक विकास परम् आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मुरैना जिला। यह क्षेत्र दस्यु समस्या से पीड़ित होने के कारण यह काफी पिछड़ा जिला रहा है। इस जिले के विकास के लिए यहाँ के ग्रामीण अंचलो का समुचित विकास करना नितांत आवश्यक है। आर्थिक विकास संबंधित योजना करने से पूर्व हमें इस क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं पर भी संक्षिप्त रूप से विचार कर लेना चाहिए। इस जिले की अर्थव्यवस्था की निम्न प्रमुख विशेषताये हैं :-

अर्चना शर्मा

व्याख्याता,
अर्थशास्त्र विभाग,
कमला महाविद्यालय,
धौलपुर, राजस्थान

राजेश शर्मा

व्याख्याता,
समाज शास्त्र विभाग,
राजकीय कन्या स्नात्कोत्तर
महाविद्यालय,
धौलपुर, राजस्थान

1. श्रम शक्ति का बाहुल्य,
2. पूँजी की न्यूनता,
3. बेरोजगारी (दृश्य एवं अदृश्य),
4. कम बचत एवं पूँजी निर्माण की कम दर,
5. ग्रामीण अंचल में शिक्षा का अभाव,
6. सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास,
7. औद्योगिक विकास का अभाव,
8. सरकारी कार्संक्रमों की जानकारी का अभाव,
9. तकनीकी शिक्षा का अभाव,

इस जिले की यह विशेषतायें दिन-प्रतिदिन बिना बोई गई अमर-बेल की तरह फैलती जा रही है और अपने प्रभाव से धीरे-धीरे इसे कमजोर बना रही है। इस अमर-बेल रुपी जाल को समाप्त करने के लिए इस जिले में ग्रामीण विकास आवश्यक हो गया है। जो मेरे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना

आज हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, राजनीतिक उथल-पुथल आदि समस्याएं द्रोपदी के चौर की तरह बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम समस्याओं के मुकाबले के लिए देश में योजना बुद्ध तरीके से विकास करना शुरू किया है। जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं एवं 20 सुत्रीय कार्यक्रमों आदि योजनायें क्रियान्वित की गई हैं। यद्यपि इन कार्यक्रमों के तहत देश विकास की कई सीढ़ियों को लांघ चुका है। मुरैना जिला जहाँ, इन योजनाओं की रोशनी का प्रभाव क्या हुआ? क्या इस क्षेत्र का ग्रामीण विकास हुआ? यह जानने के लिए इस शोध में निम्न परिकल्पनाओं को विकसित किया गया है।

1. पंचायतीराज व्यवस्था के प्रति सभी ग्रामीण व्यक्तियों में अभिज्ञान या जागरुकता समान रूप से नहीं पाई जाती है। जागरुकता तथा सहभागिता की मात्रा उनकी जाति, आय, व्यवसाय, शिक्षा तथा आयु परिवर्तन से संबंधित होती है।
2. पंचायतीराज के प्रति जिन ग्रामीण समूहों में अभिज्ञान या जागरुकता जितनी कम पाई जाती है उन समूहों में पंचायतों के गठन एवं परिचालन के प्रति उतना ही अधिक नकारात्मक या प्रतिकूल दृष्टिकोण पाया जाता है।
3. व्यक्तियों में पंचायतीराज के प्रति जागरुकता की मात्रा जितनी कम होती है, पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया को नापसन्द करने की प्रवृत्ति उनमें उतनी ही अधिक होती है।
4. लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है।
5. मानवीय एवं भौतिक साधनों को विकसित करके सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
6. ग्रामीण स्तर पर उर्जा की बचत करके विकास किया जा सकता है।
7. श्रम शक्ति को कम पूँजी के साथ ग्रामोद्योग में तकनीक परिवर्तन कर आर्थिक विकास किया जा सकता है।

8. आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण को इस क्षेत्र में प्रयोग कर मुरैना जिले का विकास किया जा सकता है।

शोध रूपरेखा

आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक समस्यामूलक तथ्य की परीक्षा वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। सामाजिक अनुसंधानों में तो इसका महत्व और भी अधिक है क्योंकि इसमें तथ्य और घटनायें बड़ी ही विचित्र परिवर्तनशील एवं जटिल प्रकृति की होती हैं।

यह अध्ययन आम जनता (ग्रामीणों से) शिक्षाविद एवं सांख्यिकी विभाग आदि से एकत्रित किये गये प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है, जो मुरैना जिले में 679 ग्राम पंचायतों तथा 1401 ग्राम तथा 10 जनपद पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित किये गये आंकड़ों पर आधारित अध्ययन है। इस जनसंख्या से साक्षरता का प्रतिशत बिन्दु भी निम्न ठहराता है। अतः ऐसी स्थिति में एक वृहद क्षेत्र को इस सीमा तक संतुलित किया जाये कि कम इकाइयों के बावजूद भी अध्ययन में विश्वसनीयता बनी रहे। समग्र का प्रतिनिधित्व हो सके इस हेतु निर्देशन पद्धति द्वारा इस कार्य को पूर्णता प्रदान की गई है।

मुरैना जिले में ग्रामीण आर्थिक विकास

पंचायतीराज में आर्थिक क्षेत्रों के विकास द्वारा ग्रामीणों की जीविकोपार्जन में वृद्धिकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाता है। पंचायतीराज में आर्थिक क्षेत्रों के विकास के जिन पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया, उनमें उद्योग धंधों का विकास, सिंचाई की व्यवस्था, पशुओं की नस्ल में सुधार, कृषि में सुधार, भूमिहीन मजदूरों की सहायता तथा सहकारी समितियों का विकास आदि प्रमुख हैं जो इस प्रकार हैं –

उद्योग धंधों का विकास

ग्राम्य जीवन यूँ तो कृषि से ही प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है परन्तु कृषि कार्य में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अनेक सामान की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास करने में ग्रामीणों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत लोगों को प्रोत्साहित करके रेशम उद्योग तथा खादी उद्योग, पोलिस्टर उद्योग आदि के प्रोत्साहन एवं विस्तार के विशेष प्रयास किये हैं। पंचायतों के द्वारा गाँव में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये प्रमुख योजनाओं – प्रधानमंत्री रोजगार, नेहरु रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मार्जिन राशि रोजगार (ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास की संजीवनी) आदि को चलाया जा रहा है। इनमें से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के चालू वर्ष 1999-2000 में लाभान्वित हितग्राही संस्था 890 रही जिसमें वर्ष में वितरित ऋण राशि 339.84 लाख तथा वर्ष में वितरित अनुदान राशि 164.42 लाख थी। जबकि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित 100% राशि को तीन भगों में यथा 20% जिला स्तर को, 15% जनपद स्तर को तथा 65% ग्राम पंचायत स्तर को वॉट दिया जाता है।

पशुओं की नस्ल में सुधार

मध्यप्रदेश के ग्रामीण जीवन में पशुओं का एक विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पशुओं की संख्या सर्वाधिक है किन्तु पशुओं की नस्ल निम्न है। ग्राम पंचायतों नये-नये पशुओं से संबंधित केन्द्रों को स्थापित करके पशुओं की नस्ल को सुधारने। उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने तथा बीमारी की स्थिति में उचित उपचार कराने आदि से सम्बन्धित कार्य कर रही है। ग्रामीण जन चूंकि अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं उन्हें पशु चिकित्सा संबंधित उचित ज्ञान भी नहीं होता। अतः पंचायत ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में उनका उचित मार्गदर्शन व सहयोग करती है। पशुओं की नस्ल में सुधार के लिये ग्रामीण की आर्थिक सहायता हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा पशुओं का बीमा किया जाता है। जिला मुरैना में न्यू इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी मुरैना, ओरियन्टल इश्योरेन्स कम्पनी, नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी एवं यूनाइटेड कम्पनी आदि कम्पनी बीमा का कार्य कर रही है। इस प्रकार पंचायत स्तर पर पशुओं की नस्ल में सुधार हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

कृषि में सुधार

मुरैना जिले का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिनमें अधिकांशतः व्यक्ति परम्परागत ढंग से ही कृषि कार्य करते हैं। जिसमें भूमि की शक्ति क्षमता शीघ्र ही क्षीण हो जाती है तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त सामग्री का चयन भी उचित ढंग से नहीं करते हैं पंचायतों के द्वारा ग्रामवासियों को कृषि संबंधित नवीन जानकारी प्रदान की जाती है। उन्हें रासायनिक खादों व अच्छे बीजों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है तथा उचित सहायता प्रदान की जाती है। कृषि कार्यों के प्रोत्साहन के लिये प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत गंगा कल्याण योजना, ट्रेक्टर का अनुदान पर वितरण, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गोबर/कम्पोस्ट खाद प्रोत्साहन, संकट हरण बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि द्वारा किसान को सहायता पहुँचाई जा रही है, जिससे खेती के प्रति लगाव बढ़ने से कृषि पैदावार बढ़ी है, जिससे जिले को अनाज के संकट से मुक्ति मिली है तथा अनाज का निर्यात भी बढ़ा है। इस प्रकार कृषि ग्रामीण विकास के साथ-2 देश का विकास करने में भी सहयोग प्रदान करती है।

सिंचाई की व्यवस्था

कृषि एक बहुत बड़ी सीमा तक प्रकृति पर ही निर्भर है, अर्थात् हमारे यहाँ कृषि का अच्छा बुरा होना वर्षा जल पर ही निर्भर करता है। वर्षा के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं में कुओं, तालाबों, नदियों आदि का सहयोग लिया जाता है। मुरैना जिले के सभी विकास खण्डों में 2002-03 में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1745, नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र 11462, कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र 127135 तथा तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र 468 है। ग्राम पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों का सुचारु रूप से विकास करने हेतु कुओं, तालाबों आदि का निर्माण करवाना सिंचाई हेतु नालियों का निर्माण करवाना व सहयोग देना, उनकी मरम्मत करवाना तथा ग्रामीण कार्यों का सम्पादन कर रही है।

भूमिहीन मजदूरों की सहायता

पंचायतीराज को प्रभावशाली बनाने हेतु अशोक मेहता समिति ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि ग्राम में भूमिहीन कृषकों एवं मजदूर वर्गों के समुचित विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्रयास किये जाने चाहिए।

इस प्रकार ग्रामों में आज भी लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं, जो कृषि में मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनके पास कृषि भूमि खरीदने हेतु आय के स्रोत व पैसा नहीं है और ये किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पंचायतों द्वारा भूमिहीन मजदूरों को उचित मजदूरी व भूमि की व्यवस्था आदि का प्रबंध किया जाता है। पंचायतें भूमिहीन मजदूरों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती है। भूमिहीन मजदूरों की सहायता के लिये भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा – “भूमिहीन खेतिहार मजदूरों के लिये निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना” संचालित की है।

सहकारी समितियों का विकास

ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीणों की समस्याओं का तात्कालिक निराकरण करने के लिए पंचायतों की सहायता से तथा सरकारी प्रयत्नों से विभिन्न सहकारी समितियों का विकास किया गया। पंचायतें ग्रामवासियों को ऐसी सहकारी समितियों से लाभ प्राप्त करने तथा समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित व प्रेरित करती हैं। ग्रामवासियों को सहकारिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करती हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण आदि दिलाने में मदद कर सकें।

निष्कर्ष

संविधान में 73वां संसोधन कर पंचायतीराज को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया फिर भी पंचायतीराज आज भी अपनी कमजोरियों से जूझ रहा है एक ओर सरपंच पतियों के दरवल की बात कही जाती है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मुद्दे पंचायतों के आगे बढ़ने में रोज़ा माने जाते हैं किन्तु मुख्यमंत्री के विधायकों व सांसदों को मिलने वाली विकास राशि में से पार्टी फण्ड के लिए हिस्सा मांगने पर भी इसे दर गुजर किया जाता है पैसे के बल पर राज्य व केन्द्र सरकारों के बहुमत को इधर से उधर ढिगाने के भी उदाहरण हैं। जब पूरी ही राष्ट्रीय राजनीति भ्रष्टाचार एवं उठा-पटक होती है तो पंचायतीराज में भी उसका असर स्वभाविक है।

इन सब के बावजूद भी पंचायतीराज लागू हो जाने के बाद ग्रामीण विकास में नई क्रांति आ रही है। परन्तु इन पंचायतीराज संस्थाओं के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ आ रही हैं। पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्व के निर्धारण के संदर्भ में 73वें संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 जी में पूरे अधिकार राज्यों की विधान सभाओं को दिये गये हैं। यह अपेक्षा की गई है कि विधान सभा इन संस्थाओं को नियम बनाकर इतनी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी कि वे प्रभावी ढंग से स्वशासी निकाय के रूप में कार्य कर सकें। सरकार ने जो भी अधिकार दिये हैं वे आधे-अधूरे व साधन विहीन हैं।

ग्राम विकास की योजनाओं की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि नीचे के स्तर पर जन भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए अर्थात् नीतियां तो अपनी जगह ठीक हैं उनका उद्देश्य ईमानदारी है परन्तु वे लोग जो प्रशासन में काबिज हैं, अपने अधिकार को आसानी से अपने चंगुल से नहीं निकलने देना चाहते। इसलिये अड़चने आना स्वभाविक है प्रशासन तंत्र सदियों से सत्ता का अधिकार अपने हाथ में लिये हैं उस तंत्र को छोड़ने में भारी असुविधा महसूस होना स्वभाविक है। पंचायतीराज व्यवस्था विश्वास, नैतिकता, निस्वार्थता की अपेक्षा करती है। मुरैना जिले में पंचायतीराज के माध्यम से विकास योजनाओं से ग्रामीण आर्थिक विकास हुआ है। इसमें ग्रामीण विकास, वित्त योजना, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, वन, मछली पालन, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत व आधुनिक दोनों प्रकार से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण जन सहयोग द्वारा हल करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में यदि देखें तो ग्राम पंचायतों न केवल ग्रामीण विकास के लिये अतिआवश्यक है वरन् यह तो एक ऐसी समिति है जिसके द्वारा लोक तांत्रिक व्यवस्था को उचित जामा (पोशाक) पहनाया जा सका। ग्राम पंचायत ही वह वास्तविक माध्यम है जिनके द्वारा स्थानिय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव की जा सकती है। ग्राम पंचायत गॉव में स्वास्थ्य नेतृत्व का विकास करने में भी सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह कर रही है। गांधी जी ने कहा था कि "हरेक गॉव में लोगो का हुकुमत या पंचायत शासन होगा, उसके पास ही पूरी सत्ता और ताकत होगी"।

सन्दर्भ सूची

- 1- S.K. Ray will help solve the problem of the poor kurukdhetra vol.xxv, III no. 10 February 16th (1980) pp.6-10
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका – मुरैना
3. हरिजन सेवक 13/04/40
4. पंचायिका दिसम्बर 2000
5. योजना 07/03/1998
6. आर्थिक जगत 30/04/1992, 21/03/1995
7. कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय
8. प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार वित्त मंत्रालय
9. जिला ग्रामीण अभिकरण वार्षिक रिपोर्ट जिला मुरैना
10. दस्तक जिला पंचायत, मुरैना